They will get Rs. 45 crores over a period of three years. That is the amount which is given.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, if you have got the list of districts, please circulate among Members.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, I will get it circulated. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why I said if there are 137 districts, let the list be circulated to all Members.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, going by the answer of the hon. Minister, the first criteria for the selection of backward districts is the agricultural output; the second is agricultural wage rate, and the third is the SC/ST population. I would like to know from the hon. Minister whether he would consider the parameters like illiteracy and health facilities because these are also very much essential to assess the backwardness of an area. I would like to draw the attention of the hon. Minister towards Srikakulam and Visakhapatnam districts. There are Ministers from Andhra Pradesh also and the Minister can as well interact with them. I would like to know whether he is in a position to include these two districts as well as Anantapur district in Rayalseema region of Andhra Pradesh.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, at present, we don't have any proposal to include these areas.

Turnover of KVIC

*124. SHRIMATI HEMA MALINI: Will the Minister of AGRO AND RURAL INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the annual turnover of the Khadi and Village Industries Commission and the number of people employed by them;

(b) whether the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is being restructured; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES (SHRI MAHABIR PRASAD): (a) to (c) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) As per the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, the functions of the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) are to plan, promote, organise and assist in the establishment and development of khadi and village industries in the rural areas. Hence the KVIC does not directly undertake any production activity. However, through its various schemes/programmes, the KVIC supports establishment and operation of industries in Khadi and Village Industries (KVI) sector with the help of its implementing agencies like registered khadi and village industries institutions and State KVI Boards and by individual entrepreneurs. The sales (annual turnover) of the units and employment in the KVI sector during the year 2003-04 were Rs. 11575.21 crore and 71.19 lakh persons respectively.

(b) Yes, Sir.

(c) In the National Common Minimum Programme, the Government has declared to revamp the Khadi and Village Industries Commission (KVIC). Towards this objective, the Government has dissolved the KVIC with effect from 14 October, 2004 and also set up a ten-Member Expert Committee with the following terms of reference:

(i) to review the existing structure, functioning and performance of the KVIC since its inception;

(ii) to review the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (No. 61 of 1956), KVIC Rules 1957, and the Regulations made thereunder and to recommend restructuring, alongwith modifications, if any, in these statutes, to achieve the objectives of (a) development of Khadi and Village Industries (KVI) and (b) making KVIC a more professional and effective body for implementation of the existing KVI programmes/schemes and/or launching new programmes/schemes with a view to enhancing employment and income generation in the rural areas and expanding the markets for (including export of) Khadi and Village Industry products; and

(iii) to recommend any other measure(s) considered necessary by the Committee to revamp the KVIC and to launch new, appropriate programmes/schemes.

SHRIMATI HEMA MALINI: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether he is aware that there are disturbing reports about many Khadi units being shut down in the rural areas of Maharashtra due to lack of financial support. This has put many women self-help groups which are running these units into trouble. What is being done to set the things right? What are the steps that the Government is taking to increase employment opportunities for the rural masses in Khadi industry?

श्री महाबीर प्रसाद: श्रीमन् माननीया सदस्य महोदया ने प्रश्न पूछा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खादी और ग्रामोद्योग के विषय में हमारी सरकार ने एक सिद्धान्त बनाया है कि खादी.. .. (व्यवधान)

श्री उपसभापति: आन्सर दे रहे हैं .. ..(व्यवधान) जवाब दे रहे हैं, केवल बैकग्राउंड बोल रहे हैं .. .. (व्यवधान) नहीं, नहीं, आप मिनिस्टर साहब को बोलने दीजिए।

SHRIMATI HEMA MALINI: I am talking about Maharashtra.

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, मैं महाराष्ट्र के बारे में बताने जा रहा हूं कि हमें इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि महाराष्ट्र में इस प्रकार की कोई चीज है। यदि इस प्रकार की कोई विशेष सूचना है तो सदस्य महोदया मुझे बताएं, मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्रीमती हेमा मालिनी: कल ही टेलीविजन में आया है। It has been reported only yesterday on television that there are problems in this regard.

श्री उपसभापति: आप सेकंड सप्लीमेंटरी पूछिए।

SHRIMATI HEMA MALINI: Sir, Khadi being environmental-friendly fabric, which is produced exclusively in India, has tremendous potential for export. Will the Government help the weavers with modern designs and attractive colour combinations to suit the present day trend? I would also like to know whether necessary fund allocation and required infrastructure would be given to the Khadi and Village Industries Commission.

श्री महावीर प्रसाद: श्रीमन् यह बात मैं मानने के लिए तैयार हूं कि खादी में उत्पादन कम हुआ है और खादी को आगे बढ़ाने के लिए, खादी में उन्नति लाने के लिए हमने एमडीए एक मार्केटिंग, जो अभियंत्रण के लिए हम खादी में एक प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें डिजाइनिंग की और हर प्रकार की सुविधा होगी, ताकि खादी को दूसरे लोग पसन्द करें और खादी का अधिक-से-अधिक हम उपभोग कर सकें। खादी में गुणवत्ता लाने के लिए मार्केट का .. .. (व्यवधान)

श्री उपसभापति: वे पूछ रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए कोई .. .. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद: सुनिए, खादी के निर्यात के संदर्भ में, निर्यात के विषय में पूछ लिया .. . . (व्यवधान)

श्रीमती माया सिंह: क्वैश्चन का आन्सर नहीं आया, सर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया. . .. (व्यवधान)

श्री उपसभापति: डिजाइन वगैरह कर रहे हैं, .. (व्यवधान) उन्होंने बता दिया, Please put your question. आप बोलिए।

SHRIMATI S.G. INDIRA: On seeing the answer given by the Minister, we find that the KVIC supports establishment and operation of Khadi and village industries. I would like to know from the hon. Minister whether his Ministry would recommend or propose to the Government for reduction in the rate of interest on loan given for starting Khadi and village industries.

श्री महावीर प्रसाद: श्रीमन् खादी में इंटरेस्ट को कम करने के लिए, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, सरकार के सामने एक विचार है और रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में इसकी एक कमेटी बनी हुई है। तो रेट में हमें कठिनाई होती है, उसे ठीक करने के लिए वित्त मंत्रालय से भी हम सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं। साथ-ही-साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एक कमेटी बनी हुई है, उससे भी हम कोशिश कर रहे हैं। खादी में चूंकि काफी लोग काम करते हैं और इंटरेस्ट अधिक होने के कारण उसमें कमी आ रही है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक-से-अधिक सुविधा रेट के संबंध में लाएं ताकि उससे हम जो ग्राहक हैं या बुनकर हैं, उत्पादक हैं, उन्हें अधिक-से-अधिक सुविधा दे सकें।

श्री उपसभापति: श्री मोती लाल वोरा।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सन् 2003-2004 में खादी की बिक्री 11575 करोड़ 21 लाख की हुई और 71 लाख 19 हजार लोगों को काम दिया गया। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2003-2004 में हुई बिक्री संतोषजनक है? महोदय, खादी की मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। आज देश में तो खादी की मांग बढ़ ही रही है, विदेशों में रहने वाले लोग भी खादी को पसंद करते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्षों की तुलना में खादी की बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है? महोदय, इस क्षेत्र में 71 लाख 19 हजार लोगों को काम देने की बात कही गयी है, तो रोजगार के क्षेत्र के कितनी बढ़ोतरी हुई है? साथ ही मंत्री जी आपने खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को अभी dissolve कर दिया है और 10 मेंबरों की कमेटी बनायी है जिसके terms of reference

आपने दिए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? महोदय, खादी कमीशन का काम इससे लगभग रुका पड़ा है क्योंकि बोर्ड नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, खादी में कमी आने के कारण और बहुत-सी रिपोर्ट्स हमारे पास आई थीं जिनके कारण हमें खादी बोर्ड को भंग करना पड़ा। अब terms of reference माननीय सदस्य को मालूम हैं और उनके आधार पर व बहुत-सी चीजों की वजह से हमने खादी बोर्ड को भंग किया। महोदय, खादी में जो गिरावट आई, उस गिरावट के कारण .. .. (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't take notice of them ....(*Interruption*)..

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, मैं पिछले कुछ वर्षों में खादी के उत्पादन, बिक्री और उससे जुड़े रोजगार के संबंध में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1997-98 में उत्पादन 624.1 करोड़ हुआ, बिक्री 745.90 करोड़ हुई और इससे 14.01 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। वहीं वर्ष 2003-2004 में 451.93 करोड़ का उत्पादन हुआ, 589.96 करोड़ की बिक्री और रोजगार घटकर 8.61 करोड़ रह गया। .. .. (व्यवधान)..

श्री उपसभापति: जरा सुनिए। वह आंकड़े दे रहे हैं। .. .. (व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, ये घबराए हुए हैं। हमारी सरकार की मंशा है कि .. .. (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप संक्षिप्त में बोलिए।

श्री महावीर प्रसाद: हमारी सरकार की मंशा साफ है और सरकार अधिक-से-अधिक रोजगार देने के लिए कोशिश कर रही है। इस स्थिति को सुधारने के लिए जो हमारा कमीशन था, उस कमीशन के संदर्भ में एक विशेषज्ञ समिति बनायी है जिसकी रिपोर्ट बहुत शीघ्र ही आने वाली है। उसकी अनुशंसा आने के बाद हम पुनर्गठन करेंगे और इस तरह से खादी के उत्पादन, बिक्री और निर्यात को सुधारने के लिए हम कोशिश करेंगे।

श्री उपसभापति: श्री दत्ता मेघे।

श्री दत्ता मेघे: महोदय, इन्होंने जो बोर्ड भंग करने की बात की, उस का क्या कारण था? क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ था? अब यह जो विशेषज्ञ समिति है यह बोर्ड बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जो रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर समिति बना रहे हैं? .. .. (व्यवधान)... इसमें पांच-छः महीने लगा रहे हैं। सर, अभी काम बहुत कम है निर्यात बहुत हो सकता है। खास तौर पर महाराष्ट्र के अन्दर ग्रामीण वर्ग में महात्मा गांधी, विनोबा भावे जी जो काम वर्धा जिले में कर रहे थे, बहुत अच्छा काम था। .. (व्यवधान)..

श्री उपसभापति: आप सवाल कीजिए।

श्री दत्ता मेघे: इसलिए समिति का गठन जल्द-से-जल्द कीजिए और जो भंग किया है, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसकी आपने इनक्वायरी की है या नहीं की है?

श्री महावीर प्रसाद: श्रीमान, माननीय सदस्य महोदय की मंशा से मैं खुद चिन्तित हूं और यह समिति आलरेडी बन चुकी है और उसकी बहुत-सी नई अनुशंसाएं आने वाली हैं। अनुशंसा आने के बाद मैं पुनर्गठन करूंगा और यह कोशिश करूंगा कि इस संदर्भ में जब हमारी समिति बन जाएगी, उसकी अनुशंसा के आधार पर कहां भ्रष्टाचार है, कहां पर कौन सी कमी है, उसे हम ठीक करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us go to the next question. Question Number 125 ...(*Interruptions*).. Question Number 125, hon. Member absent ....(*Interruptions*).. इस पर आप डिस्कशन कीजिए ...(*Interruptions*)... Question Number 126.

SHRI BALBIR K. PUNJ: Sir, I have a supplementary to ask ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRAMN: I have given opportunity to many Members ...(*Interruptions*)... आप देखिए। .. .. (**व्यवधान**).. आज 20 क्वेश्चन लिस्ट हुए हैं .. .. (**व्यवधान**) इसलिए आपको अधिकार है कि यदि क्वेश्चन के आन्सर से सैटिस्फाईड नहीं हो तो हॉफ एन ऑवर डिस्कशन नोटिस दीजिए। .. .. (**व्यवधान**) उनको बोलने दीजिए। .. ..(**व्यवधान**)... आप हॉफ एन ऑवर नोटिस दीजिए। अगर चाहें तो उस पर डिस्कशन करेंगे।

श्री जीवन राय: मंत्री जी आपने नया-नया चॉर्ज लिया..... .. (**व्यवधान**)..आपने नया-नया चार्ज लिया है.. .. (**व्यवधान**)...

SHRI BALBIR K. PUNJ: Sir, what is this? ...(*Interruptions*)...Sir, why don't you give us an opportunity to put a supplementary? ...(*Interruptions*)..This is not fair ...(*Interruptions*)....

*125. *[The questioner (Shri Karnendu Bhattacharjee was absent. For answer vide page 30].*

Non payment of statutory dues

*126. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of defaulting establishments in each State that have defaulted in the deposit of Provident Fund, Pensions, Employees Development Linked Scheme contribution, etc.;